

प्रेषक,

आनन्द स्वरूप,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं यौनी अनुभाग-1

देहरादून

दिनांक 15 जून, 2017

विषय-

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहकारी सहभागिता योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विल विभाग के शासनदेश संख्या-312/3(150)/XXVII(4)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुक्रम में आपके कार्यालय पत्र संख्या-1399/नियो0/सहभागिता/टी0एस0पी0/2017-18 दिनांक 30 मई, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सहकारी सहभागिता योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिये जाने वाले कृषि/कृषेतर ऋणों के अधीन लघु एवं सीमान्त कृषकों, बी0पी0एल0 परिवारों के कृषकों को अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किए जाने वाले ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में लेखानुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) के व्यय हेतु अवनुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त दायों का निबन्धक स्तर से सम्पन्न परीक्षण एवं त्रैमासिक प्रगति समीक्षा उपरान्त ही सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी एवं अधिम भुगतान अनुमत्त नहीं होगा। चालू वर्ष में स्वीकृत ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2018 तक ही सरस्ते ऋण के सापेक्ष वार्षिक देयता के अनुरूप ब्याज अनुदान अनुमत्त होगा।

(2) राज्य सरकार के स्तर से देय ब्याज अनुदान की गणना भारत सरकार तथा नाबार्ड के स्तर से सरस्ते ऋणों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का समायोजन करते हुए की

(2)

(5) धनराशि का योजनावार व्यय विवरण निबन्धक प्रत्येक माह बी0एफ0-13 प्रारूप पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगे।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता-राजस्व-00-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-05-सहकारी सहभागिता योजना-00 - 20-सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3. उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या:-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च 2017 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(आनन्द स्वरूप)

अपर सचिव।

संख्या-669(1)/XIV-1/2017 तदतिर्भाजित।

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारों ओवरॉय बिलडिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- वित्त-4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3- आयुक्त, कुमायू/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

4- मुख्य महाप्रबन्धक, नगार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

7- समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।

8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, देहरादून।

9- सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।

10- वज्रट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

11- प्रमारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

12- प्रमारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

13- गार्ड फाईल।